

संवधान का अनुच्छेद 311

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक पुलिस अधिकारी को मुंबई पुलिस आयुक्त ने बना वभागीय जाँच के संवधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया था।

प्रमुख बटु:

अनुच्छेद 311:

- अनुच्छेद 311 (1) कहता है कि अखलि भारतीय सेवा या राज्य सरकार के कसिी भी सरकारी कर्मचारी को अपने अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जाएगा, जसिने उसे नयुक्त कया था।
- अनुच्छेद 311 (2) के अनुसार, कसिी भी सवलि सेवक को ऐसी जाँच के बाद ही पदच्युत कया जाएगा या पद से हटाया जाएगा अथवा रैंक में अवनत कया जाएगा जसिमें उसे अपने वरिद्ध आरोपों की सूचना दी गई है तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तयुक्त अवसर प्रदान कया गया है।
- **अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षति व्यक्ती:**
 - संघ की सवलि सेवा,
 - अखलि भारतीय सेवाओं और
 - कसिी राज्य की सवलि सेवा
 - संघ या कसिी राज्य के अधीन सवलि पद धारण करने वाले व्यक्ती।
 - अनुच्छेद 311 के तहत दये गए सुरक्षात्मक उपाय केवल सवलि सेवकों, यानी लोक सेना अधिकारियों पर लागू होते हैं। वे रक्षाकर्मियों के लये उपलब्ध नहीं हैं।
- **अनुच्छेद 311 (2) के अपवाद:**
 - 2 (a) - जहाँ एक व्यक्ती की उसके आचरण के आधार पर बर्खास्तगी या हटाना या रैंक में कमी की जाती है जसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है; या
 - 2 (b) - जहाँ कसिी व्यक्ती को बर्खास्त करने या हटाने या उसके रैंक को कम करने के लये अधिकृत प्राधिकारी संतुष्ट है कि कसिी कारण से उस प्राधिकारी द्वारा लखति रूप में दर्ज कया जाना है, ऐसी जाँच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है; या
 - 2 (c) - जहाँ राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हति में ऐसी जाँच करना उचित नहीं है।

अनुच्छेद 311(2) के उपखंडों के प्रयोग से संबंधति अन्य हालया मामले:

- हाल ही में जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने अनुच्छेद 311 (2) (c) के तहत कार्रवाई की आवश्यकता वाली गतिविधियों के संदग्ध कर्मचारियों के मामलों की जाँच के लये एक वशेष कार्यबल (STF) का गठन कया।
 - इस अनुच्छेद का उपयोग कर दो शक्षकों सहति तीन सरकारी कर्मचारियों को निकाल दया गया।

कर्मचारियों को हटाने का वकिलप:

- इन प्रावधानों के तहत बर्खास्त कये गए सरकारी कर्मचारी राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण या केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) या न्यायालयों जैसे न्यायाधिकरणों में जा सकते हैं।

अन्य संबंधति संवधानिक प्रावधान:

- भारत के संवधान का भाग XIV संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधति है।
- अनुच्छेद 309 संसद और राज्य वधायिका को कर्मश: संघ या कसिी राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नयुक्त व्यक्तियों की भरती और सेवा की शर्तों को वनियमति करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 310 के अनुसार, संवधान द्वारा प्रदान कये गए प्रावधानों को छोड़कर, संघ में एक सवलि सेवक राष्ट्रपति की इच्छा से काम करता है और राज्य के अधीन एक सवलि सेवक उस राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर काम करता है।

- लेकिन सरकार की यह शक्ति निरिपेक्ष नहीं है।
- अनुच्छेद 311 किसी अधिकारी की पदच्युति, पदच्युति में कमी के लिये राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्ण शक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाता है।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/article-311-of-the-constitution>

